

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1473

दिनांक 13.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत परियोजनाएं

1473. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के शामली और सहारनपुर जिलों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति का डेटा क्या है और प्रदान किए गए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) की संख्या कितनी है, साथ ही अवसंरचना विकास की स्थिति क्या है तथा राष्ट्रीय और राज्य औसत की तुलना में इन जिलों में प्राप्त लक्ष्यों का प्रतिशत क्या है;

(ख) अपेक्षा से कम कार्यान्वयन दर रिपोर्ट वाले शामली और सहारनपुर जैसे जिलों में जेजेएम परियोजनाओं के धीमे कार्यान्वयन के कारण क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान शामली और सहारनपुर जिलों के लिए जेजेएम के अंतर्गत वित्तीय आवंटन और संवितरण का ब्यौरा क्या है तथा उपयोग की गई आवंटित निधि की प्रतिशतता क्या है;

(घ) संपूर्ण देश में प्रगति और गुणवत्ता आश्वासन के लिए केंद्रीय निगरानी दलों द्वारा आकलित परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(ङ) निगरानी करने वाले संगठनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): जेजेएम के शुभारंभ के बाद से देश में ग्रामीण परिवारों की नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 10.02.2025 तक, लगभग 12.22

करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 10.02.2025 तक, देश के 19.37 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.45 करोड़ (79.79%) से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

सहारनपुर और शामली में कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) की स्थिति-

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल परिवार	आज की तारीख के अनुसार कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन	%	राष्ट्रीय औसत	राज्य का औसत
1	सहारनपुर	468258	420348	89.77	79.77	87.59
2	शामली	165926	157689	95.04		

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इन जिलों में बुनियादी ढांचे के विकास की स्थिति निम्नानुसार है-

क्र. सं.	जिले का नाम	नलकूप			पंप हाउस		
		प्रस्तावित	पूर्ण	%	प्रस्तावित	पूर्ण	%
1	सहारनपुर	710	683	96.20%	710	681	95.92%
2	शामली	193	191	98.96%	193	173	89.64%

क्र. सं.	जिले का नाम	ओएचटी			संवितरण लाइन (किमी में बिछी)		
		प्रस्तावित	पूर्ण	%	प्रस्तावित	पूर्ण	%
1	सहारनपुर	708	175	24.72%	5931	5411	91.23%
2	शामली	182	44	24.18%	1386	1386	100.00%

शामली और सहारनपुर जिलों में जल जीवन मिशन परियोजनाओं की प्रगति ऊपर दी गई है। कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) कवरेज दोनों जिलों में क्रमशः 95.04% और 89.77% है जो राष्ट्रीय औसत और राज्य औसत से अधिक है।

(ग) वित्तीय आबंटन और निधियों का संवितरण शामली और सहारनपुर जिलों सहित पूरे राज्य के लिए है। जिला-वार निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। केन्द्र सरकार से वर्ष-वार कुल वित्तीय आबंटन और संवितरण इस प्रकार है-

वित्त वर्ष	केंद्रीय आवंटन (राशि करोड़ में)	केंद्र द्वारा जारी राशि (राशि करोड़ में)
2021-22	10870.5	5435.25
2022-23	12662.05	9496.54
2023-24	20884.45	16947
2024-25	12621.95	6310.98
कुल	57038.95	38189.77

(घ) और (ङ) भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जेजेएम के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करती रही है। क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने, तकनीकी सहायता प्रदान करने आदि के लिए समय-समय पर सम्मेलनों, कार्यशालाओं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठकों, क्षेत्र दौरों आदि सहित कई बैठकें आयोजित की जाती हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के सचिव, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन समीक्षाओं के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाएं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर वास्तविक और वित्तीय प्रगति की सूचना दी गई है और प्रदान किए गए सभी नल जल कनेक्शनों को परिवार के मुखिया की आधार संख्या से जोड़ा जाना है। जल जीवन मिशन के तहत सृजित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तृतीय पक्ष कार्यशीलता मूल्यांकन भी किया जाता है। सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिपोर्टें भेजी जाती हैं।

आज की तारीख तक विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कई क्षेत्रीय दौरे किए हैं और अब तक 7,102 गांवों का दौरा किया जा चुका है। इन दौरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

राज्य-वार क्षेत्र दौरा रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य	दौरा किए गए जिलों की संख्या	दौरा किए गए गांवों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	22	357
2	अरुणाचल प्रदेश	3	36
3	असम	27	440
4	छत्तीसगढ़	27	442
5	गुजरात	3	27
6	हरियाणा	3	42
7	हिमाचल प्रदेश	2	8
8	झारखंड	23	452
9	कर्नाटक	25	419
10	केरल	9	171
11	लद्दाख	2	41
12	मध्य प्रदेश	46	743
13	महाराष्ट्र	29	503
14	मेघालय	4	70
15	ओडिशा	27	512
16	पंजाब	10	183
17	राजस्थान	41	734
18	सिक्किम	2	20
19	तमिलनाडु	24	387
20	त्रिपुरा	1	16
21	उत्तर प्रदेश	55	936
22	उत्तराखंड	4	62
23	पश्चिम बंगाल	20	501
कुल		409	7,102

- आंकड़े जेजेएम आईएमआईएस के अनुसार हैं।